



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1070]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 4, 2016/वैशाख 14, 1938

No. 1070]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 4, 2016/ VAISAKHA 14, 1938

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2016

का.आ. 1628(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण/केन्द्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11—(क) के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना—2021 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिन्हें जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नं. भी दें, जो पठनीय हो।

संशोधन :

दि.मु.योजना -2021		
क्र. सं.	मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
19.0 भूमि संबंधी नीति		
1.	<p>19.6 विकास नियंत्रक मानक :</p> <p>iv. विकास हेतु ट्रेडेबल एफ. ए. आर. अनुमेय है, तथापि आवासीय उपयोग के मामले में ट्रेडेबल एफ. ए. आर. को 20 हेक्टेयर से अधिक की परियोजनाओं के अनुमोदन/लाइसेंस वाली उसी तरह की योजना जोनों में दूसरे विकासकर्ता समूह को ही अंतरित किया जा सकता है।</p>	<p>19.6 विकास नियंत्रण मानक :</p> <p>iv. किसी भूमि के स्वामी को 150 एफ. ए. आर. (आवासीय) की दर से हस्तांतरणीय विकास अधिकार जारी करने के मामले पर अन्यथा रूप से विचार किया जाएगा और उसमें निहित सभी अधिकार पूर्ण रूप में लैण्ड पूलिंग एजेंसी को सौंप दिए जाएंगे। विकास अधिकारों के हस्तान्तरण (टी.डी.आर.) के अनुसार एफ.ए.आर. केवल उन्हीं विकासकर्ता समूह को हस्तांतरणीय होगा, जिनके पास उसी जोन, जिसमें वह भूमि स्थित है, की आवासीय पॉकेटों में एक अन्तिम प्लॉट जो 2 हेक्टेयर से कम न हो, का अनुमोदन/लाइसेंस हो।</p>

2.	19.7 अन्य निबंधन एवं शर्तें i. इस नीति के अनुसार संपूर्ण शहरी विस्तार के उन शहरीकरण योग्य क्षेत्रों को लैंड पूलिंग की अनुमति दी जाए, जिनके लिए क्षेत्रीय योजनाएं अनुमोदित हो चुकी हैं। तथापि, इन क्षेत्रों में टी. ओ. डी. कॉरिडोरों के साथ-साथ विकास टी ओ डी नीति के अनुसार होगा।	19.7 अन्य निबंधन एवं शर्तें i. इस नीति के अनुसार संपूर्ण शहरी विस्तार के उन शहरीकरण योग्य क्षेत्रों को लैंड पूलिंग को अनुमति दी जाए, जिनके लिए क्षेत्रीय योजनाएं अनुमोदित हो चुकी हैं। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टी ओ डी) नीति लैंड पूलिंग क्षेत्रों में आने वाले एम आर टी एस कॉरिडोरों के प्रभाव जोन पर लागू नहीं होगी।
----	--	--

2. प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला दिल्ली मुख्य योजना-2021 का पाठ निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य दिवसों में उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ दि.वि.प्रा. की वेबसाइट अर्थात् www.dda.org.in पर भी उपलब्ध होगा।

[फा. सं. एफ. 3(53)2003/एमपी]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Master Plan Section)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 4th May, 2016

S.O. 1628(E).—The following modifications which the Delhi Development Authority/ Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi-2021, under Section-11(A) of Delhi Development Act, 1957, are hereby published for public information. Any person having any objections/suggestions with respect to the proposed modifications may send the objection/suggestion in writing to the Commissioner-Cum-Secretary, Delhi Development Authority, B-Block, Vikas Sadan, New Delhi-110023, within a period of thirty days from the date of issue of this Notice. The person making the objections or suggestions should also give his/her name, address and telephone/contact number(s) which should be readable.

Modifications:

MPD - 2021		
S. No.	Existing Provisions	Proposed Modifications
19.0 LAND POLICY		
1	19.6 Development Control Norms:- iv. Tradable FAR is allowed for development. However, in case of residential use, tradable FAR can only be transferred to another DE in the same planning Zones having approval/license of projects more than 20 Ha.	19.6 Development Control Norms:- iv. Owner of any land may otherwise be considered for issuance of Transferable Development Rights @ 150 FAR (residential) and all rights therein are surrendered in whole to the Land Pooling Agency. The FAR as per Transfer of Development Rights (TDR) shall be transferable only to a DE having approval/license on a final plot of not less than 2 ha. in the residential pockets of the same zone in which land is situated.
2	19.7 Other terms and conditions i. Land Pooling to be permitted as per this policy in the urbanisable areas of entire urban extension for which Zonal Plans have been approved. However, development along TOD corridors in these areas will be as per TOD policy.	19.7 Other terms and conditions i. Land Pooling to be permitted as per this policy in the urbanisable areas of entire urban extension for which Zonal Plans have been approved. Transit Oriented Development (TOD) policy would not be applicable to the influence zone of MRTS corridors lying within the land pooling areas.

2. The text of MPD-2021 indicating the proposed modifications shall be available for inspection at the office of the Dy. Director, Master Plan Section, 6th Floor, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi-110002, on all working days within the period referred above. The text indicating the proposed modifications is also available on DDAs website i.e. www.dda.org.in.

[F. No. F.3(53)2003/MP]

D. SARKAR, Commissioner-Cum-Secy.